

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1181
सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

बेरोजगारी संबंधी आंकड़े

1181. श्री मलैयारासन डी.:

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्तमान बेरोजगारी दर का विगत वर्षों की तुलना में क्षेत्र-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान युवाओं के रोजगार के आंकड़ों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र में सृजित कुल नौकरियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण कामगारों में उच्च बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा, पीएमकेवीवाई, डीडीयू-जीकेवाई और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन सहित किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने अपनी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को वास्तव में सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास, उद्योग सहयोग और नौकरी प्राप्ति हेतु सहायता में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है और 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए यह वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला (औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार सहित) अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2021-22 में 52.9%, वर्ष 2022-23 में 56.0% और वर्ष 2023-24 में 58.2% था। इसके अलावा, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2021-22 में 36.8%, वर्ष 2022-23 में 40.1% और वर्ष 2023-24 में 41.7% था।

पीएलएफएस रिपोर्टों में सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) (युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण कामगारों में क्षेत्र और आयु-वार सहित) के बारे में जानकारी <https://www.mospi.gov.in/publications-reports> पर उपलब्ध है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार (महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण कामगारों सहित) सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान एमजीएनआरईजीए, पीएमकेवीवाई और डीडीयूजीकेवाई योजनाओं के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I से III में दिया गया है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उपरोक्त के अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए एआई करियर पहल भी शुरू की है, जहां दो वर्षों की अवधि में, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण और सक्षम आर्थिक अवसर कार्यक्रम के फोकस होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं और बच्चों की सुरक्षा मुख्य बिंदु हैं। "पालना" के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों की देखभाल की निशुल्क सेवाओं का आंगनबाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से विस्तार किया है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नए प्रकार की नौकरियों/जॉब रोल्स में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए 21.11.2024 से लागू श्रम संहिताओं में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 26 सप्ताह का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:

राज्य	प्रशिक्षित/उन्मुख
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,501
आंध्र प्रदेश	5,28,234
अरुणाचल प्रदेश	98,157
असम	8,39,672
बिहार	7,60,581
चंडीगढ़	28,035
छत्तीसगढ़	2,04,543
दिल्ली	5,27,664
गोवा	10,484
गुजरात	4,71,884
हरियाणा	7,63,070
हिमाचल प्रदेश	1,76,654
जम्मू एवं कश्मीर	4,29,954
झारखंड	3,14,146
कर्नाटक	6,05,744
केरल	2,74,836
लद्दाख	4,076
लक्षद्वीप	390
मध्य प्रदेश	12,15,857
महाराष्ट्र	13,32,397
मणिपुर	1,15,021
मेघालय	58,856
मिजोरम	44,147
नागालैंड	54,055
ओडिशा	6,02,374
पुदुचेरी	35,597
पंजाब	5,63,591
राजस्थान	14,08,412
सिक्किम	19,479
तमिलनाडु	8,89,722
तेलंगाना	4,64,811
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	11,842
त्रिपुरा	1,60,367
उत्तर प्रदेश	25,09,373
उत्तराखंड	2,52,138
पश्चिम बंगाल	6,51,369
अखिल भारत	1,64,33,033

लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (दिनांक 24.11.2025 तक)

(आंकड़े करोड़ में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (24.11.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	25.86	24.15	23.95	25.55	24.23	15.83
2	अरुणाचल प्रदेश	1.28	1.59	1.51	1.60	2.04	0.99
3	असम	9.11	9.16	7.86	8.74	7.11	3.81
4	बिहार	22.61	18.03	23.64	22.05	25.02	16.27
5	छत्तीसगढ़	18.41	16.92	13.25	12.77	13.24	5.67
6	गोवा	0.0110	0.0095	0.0094	0.0043	0.0076	0.0048
7	गुजरात	4.82	5.68	4.66	4.93	4.31	2.27
8	हरियाणा	1.80	1.46	0.96	1.23	1.18	0.61
9	हिमाचल प्रदेश	3.36	3.71	3.08	3.44	3.95	1.50
10	जम्मू और कश्मीर	4.07	4.06	3.09	3.75	4.09	2.23
11	झारखंड	11.76	11.32	9.15	10.97	10.09	8.01
12	कर्नाटक	14.80	16.32	12.58	13.85	13.12	6.25
13	केरल	10.23	10.60	9.66	9.95	9.08	5.01
14	लद्दाख	0.21	0.19	0.20	0.20	0.22	0.14
15	मध्य प्रदेश	34.18	29.99	22.59	19.96	18.97	13.84
16	महाराष्ट्र	6.79	8.25	7.88	11.60	16.22	9.86
17	मणिपुर	3.31	3.03	0.74	1.46	2.45	1.31
18	मेघालय	3.84	3.94	2.89	3.25	3.21	1.53
19	मिजोरम	1.99	2.01	2.02	2.04	1.98	1.23
20	नागालैंड	1.80	1.93	1.97	1.79	0.94	0.80
21	ओडिशा	20.81	19.78	18.51	18.28	11.93	7.94
22	पंजाब	3.77	3.31	3.21	3.51	3.14	1.87
23	राजस्थान	46.05	42.43	35.71	37.52	31.66	14.42
24	सिक्किम	0.37	0.34	0.32	0.34	0.34	0.21
25	तमिलनाडु	33.39	34.57	33.47	40.87	30.61	11.22
26	तेलंगाना	15.80	14.58	12.19	12.09	12.23	5.52
27	त्रिपुरा	4.37	4.26	3.35	3.70	3.53	1.95
28	उत्तर प्रदेश	39.30	32.55	31.12	34.52	33.65	17.09
29	उत्तराखंड	3.04	2.43	2.06	1.97	1.90	0.58
30	पश्चिम बंगाल	41.40	36.42	3.79	0.02	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार	0.0261	0.0114	0.0129	0.0124	0.0088	0.0027
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0.0000	0.0000	0.0000	0.0041	0.0299	0.0099
33	लक्षद्वीप	0.0002	0.0001	0.0005	0.0004	0.0000	0.0000
34	पुदुचेरी	0.1057	0.0615	0.0830	0.2189	0.1078	0.1147
	योग	388.68	363.09	295.51	312.17	290.60	158.09

(एनआरईजीए सॉफ्ट के अनुसार) और एनआरईजीए वेबसाइट से भी

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भौतिक उपलब्धि:

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 20-21		वि.व. 21-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 अक्टूबर 2025 तक 10.11.2025 तक (केबी)	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2177	1606	2135	18616	17070	19829	18045	10328	9033	8913	203
2	अरुणाचल प्रदेश	28	33	233	71	608	295	678	315	684	265	20	109
3	असम	1966	3296	3553	916	12532	6817	10615	8571	5231	4127	1089	337
4	बिहार	2687	2745	7099	2491	11516	9005	6733	7226	1709	1885	96	199
5	छत्तीसगढ़	1109	3683	6499	2883	9742	8484	3045	3958	1170	1759	582	267
6	गुजरात	240	875	830	599	2912	1450	3960	2729	3544	2584	1115	1111
7	हरियाणा	26	1213	1772	680	5554	2685	8478	4882	4492	3700	2719	1150
8	हिमाचल प्रदेश	0	117	334	10	3967	2175	4324	3187	3084	2273	2367	1395
9	जम्मू और कश्मीर	3454	1945	2300	1102	5459	2754	1177	1245	1767	636	1088	628
10	झारखंड	1050	1879	4035	1354	10228	7343	11340	8157	6607	4911	3014	1019
11	कर्नाटक	769	1649	1442	673	3757	2813	3795	2656	1797	1914	398	405
12	केरल	3053	2931	3219	1097	8623	5224	5212	4078	3052	2572	602	600
13	मध्य प्रदेश	903	969	6825	3977	15653	11287	12107	10538	5097	4756	2769	1425
14	महाराष्ट्र	874	3319	348	1612	7830	4020	6381	4614	7761	4347	2310	967
15	मणिपुर	338	387	811	139	1921	1266	782	854	263	356	1363	374
16	मेघालय	83	158	456	241	2165	1353	1630	1352	1642	761	582	453
17	मिजोरम	37	88	105	94	344	349	725	499	723	474	518	96
18	नागालैंड	221	278	1009	614	2371	1409	1714	1592	804	570	509	400
19	ओडिशा	7978	7729	10474	4828	16778	13248	3997	5330	947	1095	1365	459
20	पंजाब	2922	1931	6976	4188	8121	7020	11803	8805	1979	3560	4796	817
21	राजस्थान	981	1759	3096	3130	6092	6209	7233	4218	5376	4532	4977	1005
22	सिक्किम	0	43	90	0	859	384	1123	720	255	393	119	8
23	तमिलनाडु	213	1286	8228	2941	15225	10648	13411	10206	5274	4803	2613	753
24	तेलंगाना	2752	1436	3177	2494	7094	4564	92	230	2560	1271	2554	928
25	त्रिपुरा	21	609	1049	193	2244	1189	2126	1336	913	694	425	153
26	उत्तर प्रदेश	1540	4068	16898	3765	36567	21921	45215	33458	18080	16245	7408	2373
27	उत्तराखंड	367	416	3645	917	8248	4409	6026	5306	1894	2821	1907	566
28	पश्चिम बंगाल	521	2544	732	2424	9596	4774	4979	5979	3172	1969	880	1017
29	पुदुचेरी			165	44	844	343	956	919	436	444	305	104
30	अं. एवं नि. द्वीप समूह			0	0	133	38	547	225	242	196	95	94
	योग	38289	49563	97006	45612	235599	160546	200033	161230	100883	84946	57498	19415

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय